IJRAR.ORG E-ISSN: 2348-1269, P-ISSN: 2349-5138

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND ANALYTICAL REVIEWS (IJRAR) | IJRAR.ORG

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

स्ववित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन मे चुनौतियॉ

अरविन्द कुमार
सहा0 आचार्य (शिक्षा शास्त्र)
जे0एस0कॉलेज, बदायूँ, उ0प्र0

सार

भारतीय शिक्षा प्रणाली की पहुॅच के विस्तार में निजी शिक्षण संस्थानों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में देश के 70 उच्च शिक्षा संस्थान निजी क्षेत्र है और 70 से अधिक शिक्षा के लिए निजी संस्थान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्च शिक्षा अवसंरचना, छात्रवृत्ति और अनुदान से सम्बन्धित तीन बंदोबस्ती की स्थापना के लिये प्रोत्साहित करने हेतु कर प्रणाली में मूलभूत बदलावों को बढ़ावा देने में सहायता करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों की आवश्यकता है, जिससे केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वयन तथा सहयोग, नये कानूनों का निर्माण या मौजूदा कानूनों में संशोधन सहित अन्य विधायी हस्तक्षेप, वित्तीय संसाधनों की वृद्वि और नियामकीय सुधार आदि शामिल है।

इस नीति में उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम, अवसंरचना, शिक्षण प्रणाली आदि में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव किया गया है, हालॉकि इस बदलावों को लागु करने के लिये संसाधनों का प्रबंध एक बड़ी चुनौति है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पॉच स्तम्भों पर केन्द्रित है– वहनीयता, अभिगम्यता, गुणवत्ता, न्यायपरस्ता और जवाबदेही। नई शिक्षा नीति 2020 ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ली है और 2040 तक भारत में प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों को बदलने के लिए एक व्यापक ढ़ांचा तैयार किया है। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में महत्वपूर्ण सुधारों की मांग करती है जो अगली पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिये तैयार करती है जिससे वो नये हिजिटल युग में प्रतिस्पर्धा कर सके। नई शिक्षा नीति बहु–विषयकता, हिजिटल साक्षरता, लिखित संचार–समाधान, तार्किक तर्क और व्यावसायिकता प्रदर्शन पर अत्यधिक प्रभाव डालती है। इस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम, अवसंरचना, शिक्षण प्रणाली आदि में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि बदलावों को लागु करने के लिये संसाधनों का प्रबंध एक बड़ी चुनौति होगी। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में महत्वपूर्ण सुधारों की मांग करता है जो अगली पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिये तैयार करेगी। जिससे वो नये डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। यह नई शिक्षा नीति 2020 बहु विषयकता, डिजिटल साक्षरता, लिखित प्रदर्शन पर अत्यधिक प्रभाव डालेगी। यह छात्रों के समग्र विकास और प्रगति को ध्यान में रखते हुए लाई गयी है।

मुख्य शब्द – शिक्षक शिक्षा, चुनौतियॉ, शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र।

प्रस्तावना –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को भारत के केन्द्रिय मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया था, नई शिक्षा नीति 2020 ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, की जगह ले ली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ–साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करती है। भारत द्वारा 2015 में अपनाये गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्ष विकास एजेंडा के

अनुसार विश्व में 2030 तक 'सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिये जाने' का लक्ष्य है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिये संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता है ताकि सतत विकास के लिये 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण टार्गेट लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21 वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिये अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21 वीं सदी की शिक्षा के लिये आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एसडीजी 4 शामिल है, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। यह नीति इस सिद्वांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्यात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है।

समस्या कथन –स्ववित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में चुनौतियॉ।

अध्ययन के उद्देश्य –

- स्ववित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की रूपरेखा।
- उच्चतर गुणवत्ता युक्त ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों का निर्माण और विकास करना जो स्थानीय/भारतीय भाषाओं में या द्विभाषी रूप से शिक्षण करायें।
- बेहतर भागीदारी और सीखने के परिणामों के लिये प्रौघोगिकी का निर्माण और विकास।
- उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से जुड़ी लागत और इस दौरान हुई आर्थिक अवसरों की हानि को कम करना।
- उच्चतर शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्तियों से जुड़ी जागरूकता के लिये प्रचार–प्रसार
- उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों को अधिक रोजगारपरक बनाना।
- भारतीय भाषाओं और द्विभाषी रूप से पढ़ाये जाने वाले अधिक डिग्री पाठ्यक्रम विकसित करना।
- पाठ्यक्रम सहित उच्च शिक्षा संस्थानों के सभी पहलुओं द्वारा संकाय सदस्यों, परामर्शदाताओं और विघार्थियों को जेंडर–पहचान के प्रति संवेदनशील और समावेशित करना।
- सार्वजनिक और निजी दोनों ही तरह के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में एसडीजी को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवत्ति प्रदान करना।
- विकास की ओर उन्मुख जिलों में उच्चतर गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षण संस्थान बनाकर और संख्या में एसडीजी लिये हुये विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाकर पहुॅच को सुधारना।

अनुसंधान क्रिया विधि –

प्रस्तुत शोघ कार्य का क्षेत्र विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक, आलोचनात्मक, मूल्यांकनपरक और व्याख्यात्मक है। प्राथमिक व माध्यमिक स्त्रोतों के माध्यम से उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ के साथ नई शिक्षा नीति 2020 के सम्पूर्ण अध्ययन पर जोर दिया गया है।

प्राथमिक स्त्रोत – भारत सरकार द्वारा जारी नई शिक्षा नीति 2020 के मूल पाठ का उपयोग किया गया।

द्वितीयक स्त्रोत – नई शिक्षा नीति 2020 पर संदर्भित पुस्तकें। शोध पत्र, शोध प्रबंध, शोध पुस्तकें, व्यक्तिगत साक्षात्कार, विकिपीडिया, ब्रिटानिका और अन्य वेबसाइटें आदि का उपयोग किया गया।

अध्ययन का महत्व –

इस नीति के माध्यम से शिक्षा के पाठ्यक्रम, अवसंरना, शिक्षण प्रणाली आदि में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव किया जाये। स्वायत्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में नई शिक्षा नीति 2020 के कियान्वयन में 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जायेगा। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विश्वस्तरीय अनुसंधान और उच्च गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर जोर दिया गया है। अधिक उच्चतर शिक्षण संस्थानों तथा उच्चतर शिक्षा के और अधिक कार्यक्रमों में मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जायेगा ताकि पहुॅच और सकल नामांकन अनुपात दोनों में बढ़ोत्तरी हो सके। शिक्षा के विभिन्न आयामों को बेहतर बनाने के लिये प्रौघोगिकी के सभी प्रकार के प्रयोग व एकीकरण को समर्थन दिया जायेगा एवं अंगीकृत किया जायेगा। विघालय एवं उच्चतर शिक्षा दोनों क्षेत्र में शिक्षण, मूल्यांकन नियोजन, प्रशासन आदि में सुधार हेतु प्रौघोगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदन–प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिये एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौघोगिकी मंच का निर्माण किया जायेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य प्रौघोगिकी को अपनाये जाने और किसी क्षेत्र विशेष में उसके उपयोग से सम्बन्धित निर्णयों को सुगम बनाना होगा।

साहित्य की समीक्षा–

इसमें पिछले अध्ययनों की समीक्षा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जो इस अध्ययन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है। इसमें नई शिक्षा नीति 2020 और विशेष रूप से उच्च शिक्षा से सम्बन्धित अध्ययनों पर किये गये कार्यो की एक झलक देखने को मिलती है। नई शिक्षा नीति 21 वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ले ली। सबके लिये आसान पहुॅच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिये अगस्त 2030 के अनुकूल और इसका उद्देश्य 21 वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समय, लचीला बनाते हुये देश को एक जीवंत समाप्त और प्रत्येक छात्र में निहित अदवित्तीय क्षमताओं को सामने लाना है।

नई शिक्षा नीति 1986 –

- स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर यह पहली कोठारी कमीशन की सिफारिशों पर आधारित थी।
- शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घाषित किया गया।
- शिक्षा पर केन्द्रीय बजट का 6 प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य रखा।
- इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविघालय के साथ ओपन युनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया।
- ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिये महात्मा गॉधी के दर्शन पर आधारित ''ग्रामीण विश्वविघालय'' मॉडल के निर्माण के लिये नीति का आहान किया गया।

नई शिक्षा नीति 1992 –

- नई शिक्षा नीति में संशोधन का उद्देश्य देश में व्यावसायिक और तकनीकि कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था।
- इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा तथा राज्य स्तर के संस्थानों के लिये राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा निर्धारित की।
- इसने प्रवेश परीक्षाओं की बहुलता के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों पर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बोझ को कम करने की समस्याओं को हल किया।

शिक्षा नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता –

- बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी।
- शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।
- भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

नई शिक्षा नीति 2020 –

नई शिक्षा नीति में शिक्षा की पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जी0डी0पी0 के 6 प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' करने को भी मंजूरी दी गई है।

भाषायी विविधता को संरक्षण – स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

चुनौतियॉ –पिछले 5 वर्षो में शिक्षा पर निवेश को बढ़ाने की बजाये इसमें लगातार कटौती हुई है। इसलिए उच्च शिक्षा में बड़ी चुनौति बुनियादी सुविधाओं का अभाव और गुणवत्ता में आई कमी है।

विश्वविघालय में संबद्व विघालयों का बढ़का बोझ, पाठ्यक्रमों में बदलाव की मांग और ड्रापआउट विघार्थियों की बढ़ती संख्या असली चुनौतियॉ है, जिनका संबंध भी कहीं–न–कहीं सार्वजनिक शिक्षा के ढहते ढ़ांचे और निजीकरण से ही है। वहीं उच्च शिक्षा में अध्यापकों के रिक्त पद से जुड़े ऑकड़े खुद अपनी हकीकत बताते है। इसका बुरा असर उच्च शिक्षा की अकादमिक गुणवत्ता पर पड़ा है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब 20 विश्वविघालय और 500 कॉलेज थे। वर्तमान में 1000 से अधिक विश्वविघालय और 40,000 से अधिक कॉलेज है। संख्या की दृष्टि से उच्च शिक्षा में विकास होता दिखता है, लेकिन गुणवत्ता के मानकों पर यह दुनिया के अनेक देशों के मुकाबले पीछे है। कॉलेज खुलने से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है।

भारत की नई शिक्षा नीति बेहतर होने के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों के पुनर्गठन और एकत्रीकरण की सिफारिश करती है। इसके मुताबिक यदि किसी शिक्षा संस्थान में विघार्थियों की संख्या कम है तो उसका किसी अन्य शिक्षा संस्थान में विलय कर दिया जायेगा। ऐसा हुआ तो आशंका है कि देश के दूरदराज के क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के प्रसार और प्रोत्साहन का कार्य रुक जायेगा। तथा इससे कई ग्रामीण, पहाड़ी और जनजातीय अंचल से शिक्षा संस्थान बंद हो जायेंगे। कोरोना महामारी के दौरान इन क्षेत्रों के विघार्थियों की पढ़ाई पहले ही बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

डपसंहार –

अंत में सम्पूर्ण प्रपत्र से यह ज्ञात होता है कि नई शिक्षा नीति 2020 का स्वयत्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा में तकनीकि शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रोघोगिकी शिक्षा का विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा का विशेष कार्य बालक का ज्ञान, कौशल, मूल्य आदि का विकास करना है। नई शिक्षा नीति 2020 की **5+3+3+4** प्रणाली 2030 तक पूरे देश में लागु हो जायेगी। इस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम, अवसंरचना, शिक्षण प्रणाली आदि में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि बदलावों को लागु करने के लिये संसाधनों का प्रबंध एक बड़ी चुनौति होगी। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में महत्वपूर्ण सुधारों की मांग करता है जो अगली पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिये तैयार करेगी। जिससे वो नये डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। यह नई शिक्षा नीति 2020 बहु विषयकता, डिजिटल साक्षरता, लिखित प्रदर्शन पर अत्यधिक प्रभाव डालेगी। यह छात्रों के समग्र विकास और प्रगति को ध्यान में रखते हुए लाई गयी है।

संदर्भ सूची –

- https://bachpanexpress.com/higher-education/05-2020-580641
- https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-etiturials/implementation-plan-to-help-nep-2020-work
- https://www.ofonline.org/hindi/research/challenges-new-education-policy-2020-education-in- indian/
- https://www.education0gov.in/sites/uploadfiles//mhrd/files/nep final english 0.pdf
- https://en.wikipedia.org/wiki/national policy 2020
- saxena mang. K., anu G.S. new education policy on higher education: prabhat prakashan
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, भारत सरकार नई दिल्ली
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार नई दिल्ली